THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) No, Sir

(b) Does not arise.

(c) Does not arise

(d) No, Sir During 1977-78 STC arranged import of Polyester filament yarn to supplement indigenous production

बीस, पचास तथा सौ रु० के नोटों का विमुद्रीकरण

5125. **श्री भारत भूषण :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का बीस पचास तथा सौ रुपये के करेंसी नोटो का विमुद्रीकरण करने का विचार है

(ख) यदि हां तो ऐसा कब तक किया जायेगा और

(ग) बीस, पचास तथा सौ रुपये के कितने करेंसी नोट इस समय चलन मे है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफीकारउल्ला) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नही होता ।

(ग) जनवरी, 1978 के अन्त तक 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये के चलनसार करेंसी नोटो की सख्या निम्नलिखित है —

मूल्य वर्ग	नोटो की सख्या
20 रुपये	30 6 करोड
50 रुपये	18 3 करोड
100 रुपये	41 1 करोड

ये आकडे अनन्ति है ।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को और 1951-52 में केन्द्रीय ऋणों की बकाया राशि और 1977-78 के लिए मंजूर केन्द्रीय ऋण

5126. **श्री राम किशन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) राज्यो और सघ राज्य क्षेत्रो की और 1951-52 मे केन्द्रीय ऋणो की बकाया राशि क्या थी और 31 दिसम्बर, 1977 के दिन की राशि क्या है, और

(ख) राज्यो और सघ राज्य क्षेत्रो के लिए वर्ष 1977-78 के लिए कितनी राशि के केन्द्रीय ऋण मजर किये गये और पिछले ऋण की किश्तो तथा ब्याज की राशि को काट कर उन्हे वास्तव मे कितनी राशि दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) भारत के नियत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार किए गए, वित्त लेखो के अनुसार केन्द्रीय ऋणो की बकाया रकमो के बारे मे सूचना इस प्रकार है —

(करोड रुपयो मे)

(i) 1951-52 के अन्त मे राज्यो की बकाया रकमे (1951-52 मे कोई सघ राज्य क्षेत्र नही था)	244
(ii) 1975-76 के अन्त मे राज्यो व सघ राज्य क्षेत्रो की बकाया रकमे	9783

सरकारी खाते 31 मार्च, को समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किये जाते है । 1976-77 के वित्तीय खातों को अभी अन्तिम रूप नही दिया गया है ।

(ख) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ही वास्तविक आकडो का पता लगेगा और इन्ही आकडो को ही अतिम रूप दिया जाएगा । परन्तु 1977-78 के सशोधित अनुमानो के आधार पर वर्ष से सम्बन्धित सूचना इस प्रकार है —

(करोड रुपयो मे)

(1) राज्यो और सघ राज्य क्षेत्रो की सरकारो का केन्द्रीय ऋणो का सकल भुगतान	2020
(i1) राज्यो और सघ राज्य क्षेत्रो की सरकारो से केन्द्रीय ऋणो की वसूली	860
(iii) केन्द्रीय ऋणो पर राज्यो और सघ राज्य क्षेत्रो की सरकारो द्वारा की गई ब्याज की अदायगिया	524

चलन मे विमुद्रीकृत करेसी नोट

5127 **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि

(क) क्या यह सच है कि अधिक मूल्य वाले करेसी नोट जो विमुद्रीकरण के दिन चलन म थे, जमा करने के लिए नियत अन्तिम तारीख तक जमा नही किए गये थे और मूल्यवार उनकी सख्या क्या है

(ख) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रो म प्रकाशित इन समाचारपत्रो की ओर दिलाया गया है कि लोगो ने अपने विदेशी बैंक लेखो के माध्यम से उक्त नोट बदलवाने मे जाल-साज की और सरकार के पास इस बारे मे पूर्ण जानकारी एव तथ्य क्या है, और

(ग) क्या सरकार का विचार मामले की जाच करने का है और यदि हा, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफीकारउल्ला) : (क) जी, हा । यद्यपि सम्पूर्ण आकडे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अभी तक सकलित किए जा रहे हैं, फिर भी बैंक के द्वारा उपलब्ध अनन्तिम आकडो से यह ज्ञात होता है कि लगभग 16 करोड रुपये की कीमत के ऊचे मूल्य वर्ग के नोट निश्चित की गई अतिम तिथि तक समर्पित नही किए गए थे । मूल्य वर्ग वार आकडे उपलब्ध नही है ।

(ख) जी, नही ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नही होता ।

Sale of Imported Raw Groundnut Oil to Private Refineries by STC

5128 SHRI G S REDDI Will the Minister of COMMERCE CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state

(a) whether State Trading Corporation has decided to sell imported raw groundnut oil to private refiners,

(b) if so, whether this will not push up prices of refined oil through manipulation by private refiners and

(c) if so what steps are being taken by the STC to protect the consumer and also ensure quality?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL) (a) to (c) State Trading Corporation is considering a proposal to call for offers for sale of the imported groundnut oil The terms and conditions of sale are yet to be finalised